**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : और आप समझ रहे हैं मेरी मुश्किल!

**श्री सभापति** : ये भी समझ रहे हैं, पूरा हाऊस समझ रहा है। ... ( **व्यवधान** )... लालू जी, देखिए, आपने बता दिया है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। ... ( **व्यवधान** )...

**श्री लालू प्रसाद** : मैंने क्या किया, यह अखबार में ....

**श्री सभापति** : अखबार में छपा है, ठीक है ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री लालू प्रसाद** : महोदय, राम जेठमलानी जी माननीय सांसद है और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं...

**श्री सभापति** : वह ठीक है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।... ( **व्यवधान** )...

**श्री लालू प्रसाद** : यह अखबारों में छपी हुई बात है, इसको समझना चाहिए आपको!

**श्री सभापति** : लालू जी, यह संभव नहीं है कि अखबारों में जो छपे उसका जबाब देने के लिए उसी दिन मंत्री आ जाएं। यह संभव नहीं है। आपने आज ही तो कहा है।

**श्री लालू प्रसाद** : सभापति जी, ये इसे देखें और देखकर कार्रवाई करें।

**श्री संजय निरुपम** : सभापति जी, एक मिनट-एक मिनट।

**श्री सभापति** : कोई एक मिनट नहीं। नेक्सट क्वेश्चन।

## उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया देय राशि

*665. **श्रीमती प्रेमा करियप्पा** :††

**श्री मोती लाल वोरा** :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का अभी तक चीनी मिलों पर कितना बकाया है और उसमें पिछले वर्ष का देय कितना है;

(ख) उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी व सरकारी चीनी मिलें कितनी हैं और इनमें से कितनी मिलें चल रही हैं;

(ग) किसानों को गन्ने का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा चीनी मिलों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) क्या सरकार को किसानों का पूरा गन्ना न खरीदे जाने की कोई शिकायतें मिली हैं; और

---

††सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ( श्री शरद यादव )** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2003 को स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2002-2003 के लिए 1139.77 करोड़ रुपये तथा 2001-2002 चीनी मौसम के लिए लगभग 24.98 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया था।

2. उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में संस्थापित और कार्यरत चीनी मिलों की संख्या के संबंध में (तथा पेराई कार्य के आरम्भ होने के संबंध में) सूचना नीचे दी गई है :—

| क्रम सं. | क्षेत्र | 31-3-2003 की स्थिति के अनुसार संस्थापित चीनी मिलें | उन चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने चीनी मौसम 2002-2003 के लिए पेराई कार्य आरम्भ किया |
|---|---|---|---|
| 1. | निजी | 58 | 51 |
| 2. | सहकारी | 27 | 27 |
| 3. | सार्वजनिक | 22 | 22 |
| | **कुल :** | 107 | 100 |

3. वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए उत्तर प्रदेश में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों से 95 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में गन्ना मूल्य अदा करने के लिए कहा गया है जबकि निजी चीनी मिलें गन्ना किसानों तथा संबंधित चीनी मिलों के बीच हुई सहमति के अनुसार किसानों को अग्रिम के रूप में कुल मिलाकर 70 रुपये से 90 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में मूल्य अदा कर रही हैं।

4. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ने की खरीद नहीं करने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

**Outstanding dues of sugarcane growers in Uttar Pradesh**

†*665. SHRIMATI PREMA CARIAPPA : ††
SHRI MOTILAL VORA :

†Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Prema Cariappa.

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the outstanding dues of sugarcane growers against the sugar mills in Uttar Pradesh, as on date, togetherwith the dues pertaining to the previous year;

(b) the number of private, co-operative and Government sugar mills in Uttar Pradesh togetherwith the number of mills which are in operation;

(c) the rate of sugarcane being paid to the farmers and the facilities provided by Government to sugar mills;

(d) whether Government have received complaints regarding non-purchasing of the entire sugarcane; and

(e) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (e) As per the information furnished by the Government of Uttar Pradesh, the outstanding dues of the sugarcane growers for the sugar season, 2002-2003 (as on 28th February, 2003) were Rs. 1139.77 crores and an amount of about Rs. 24.98 crores, pertaining to the 2001-2002 sugar season, was outstanding to the cane growers.

2. The information in respect of the number of installed and working sugar mills of the private, cooperative and public sectors in Uttar Pradesh (and in regard to the commencement of crushing operations) is given below :

| Sl. No. | Sector | Installed sugar mills (As on 31-3-2003) | Sugar mills commence crushing operations for 2002-2003 sugar season |
|---|---|---|---|
| 1. | Private | 58 | 51 |
| 2. | Cooperative | 27 | 27 |
| 3. | Public | 22 | 22 |
| | TOTAL : | 107 | 100 |

3. For the current 2002-2003 sugar season, the cooperative and public

sector mills in U.P. have been asked to pay cane price in the range of Rs. 95-100 per quintal while the private sugar mills are, by and large, paying price in the range of Rs. 70 to 90 per quintal, as per agreement between cane growers and the concerned sugar mills, as advance to the growers.

4. No complaint has so far been received in regard to non-purchase of the entire sugarcane by the sugar mills in U.P.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Mr. Chairman, Sir, in Uttar Pradesh, the sugarcane growers have harboured complaints against the sugar mill management for underweighment of sugarcane as also delayed payments which are far less than minimum procurement price announced by the State and the Centre, from time to time. In the reply, it has been stated that the State Government of Uttar Pradesh has fixed Rs. 95 per quintal of sugarcane as State Advisory Price, and farmers are demanding this price. The Centre has fixed Rs. 70-90 per quintal as Minimum Support Price. The farmers' dues have gone up mainly because of the difference between the SAP and MSP fixed by the State and the Centre respectively... *(Interruptions)*...Sir, two days back, it has been reported in the newspapers, ''UP farmers left guessing as cane price war goes on.''

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I would like to know from the hon. Minister, what is the reason for the failure to find a solution, despite strong intervention by the Centre through pressure from Food Minister, Agriculture Minister, Law Minister and even the Chief Minister of Uttar Pradesh?

**श्री शरद यादव :** सभापति जी, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है वह निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है। सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम उठाए हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से किसानों की बाबत हमारे पास जो पैसा है वह तेरह सौ करोड़ रुपए के करीब है। इसमें से हमने बीस लाख बफर स्टाक बनाकर सात सौ छियासी करोड़ रुपए रखे हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए पचास करोड़ रुपए, मॉडर्नाइजेशन एण्ड रिहैब्लीटेशन के लिए एक सौ पचास करोड़ रुपए, केन डेवलेपमेंट के लिए बीस करोड़ रुपए, बगास और को-जनरेशन के लिए सौ करोड़ रुपए, एथेनोल के लिए पचास करोड़ रुपए हैं। हमारे पास बफर स्टाक है। पहले हमेशा ऐसा होता था कि गन्ना उत्पादन साइकल से चलता था लेकिन चार वर्षों से जो उत्पादन है वह बढ़ता जा रहा है। चीनी के दाम कम हुए हैं...( **व्यवधान** ) ...

**श्रीमती सरला माहेश्वरी :** गन्ना किसानों को दाम मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं...( **व्यवधान** )...

**श्री शरद यादव :** माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं, जब आप पूछेंगी तो आपको भी जवाब दूंगा। इन्होंने पूछा है कि जो दिक्कत है उस दिक्कत के बारे में सरकार क्या कर रही है ? यह बहुत गंभीर समस्या है। इस पर प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी, 2003 को शरद पवार के साथ को-ऑपरेटिव्स की एक मीटिंग बुलाई थी। 27 अप्रैल को भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, वहां की गन्ना मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई है चार तारीख को उसकी बैठक बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में असली समस्या यह है कि यहां स्टेच्युट्री मिनिमम प्राइस एनाउंस किए गए हैं। यह पहले चौंसठ रुपए था अब उनहत्तर रुपए हो गया है इसलिए जो प्राइवेट मिल ओनर्स हैं, जो निजी उद्योग के लोग हैं वे कोर्ट में चले गए हैं, उन्होंने स्टे ले लिया है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाकर को-ऑपरेटिव और सरकारी मिलों को नाइन्टी फाइव रुपए पे करने का आदेश लिया है लेकिन जो निजी चीनी उद्योग के मलिक हैं वे एम. एस. पी. और स्टेट एडवाइजरी प्राइस में रेट का जो अंतर है उस अंतर को देने के संबंध में कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं। उनसे अभी चार तारीख को मीटिंग हुई है। इस पर वार्ता जारी है। हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं वह पूछने का काम करें मैं सब तरह से जवाब देने के लिए तैयार हूं। सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है और आगे भी जो कदम उठाने हैं उन्हें हर प्रकार से उठाने के लिए तैयार है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : We want to know what the Government is doing.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I want to know whether, normally mill owners enter into contract with farmers in regard to supply price and time of payment, and, if so, who is the authority to enforce such contracts and how many sugar mills, in both the Government and private sectors, have been closed in UP?

**श्री शरद यादव :** इसका जवाब तो दे दिया है।

**श्री मोती लाल वोरा :** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सन् 2001-2002 की बकाया राशि 24 करोड़ 48 लाख रुपए है और सन् 2002-2003 की बकाया राशि 1139.77 लाख रुपए है, कुल मिला करके 1164 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रयास की प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा, लेकिन उसके साथ यह भी जानना चाहूंगा कि उनके इतने प्रयास करने के बाद भी क्या मिल मालिक सरकार पर इतने हॉवी हैं कि वे गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं दे पाए ? मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल में एक बैठक बुलाई ...( **व्यवधान** )... एक बार जवाब दे दें ...( **व्यवधान** )।

**श्री सभापति :** वह इन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी।

**श्री मोतीलाल वोरा :** माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बैठक तब बुलाई जब गन्ने का सीजन समाप्त हो गया। जो निजी मिल मालिक हैं वे आज 65 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं जबकि वायदा किया गया था कि 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा। अब जबकि एक साल का समय पूरा होने को आया है और प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा और गन्ना मंत्री को बुलाना पड़ा, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके बाद भी आज जो 1164 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि मिल मालिकों की तरफ किसानों की बकाया है, उसकी वसूली के लिए क्या सरकार सख्ती से कोई कार्यवाही करेगी ?

**श्री शरद यादव :** श्रीमन्, वोरा जी ने दो-तीन सवाल पूछे हैं, मैं उनका एक-एक करके जवाब देना चाहूंगा। मेरी आपसे विनती भी होगी कि उसमें जल्दबाजी न करें, इसलिए कि यह एक गंभीर समस्या है। अब यदि मैं भी नहीं कह पाऊंगा तो मुझे भी असंतोष रहेगा और जब मैंबर्ज को भी पता नहीं चलेगा तो उनको भी असंतोष रहेगा। इसलिए इन्होंने एक-एक करके जो बातें उठाई हैं, उनका मैं एक-एक करके जवाब देता हूं। सभापति जी, एक तो वोरा जी ने कहा कि भारत सरकार चिंतित नहीं है। दिसंबर में कृषि सीजन के पहले प्रधानमंत्री जी के यहां, शरद पवार, मैं और विखे पाटील जी, जो यहां हैं, उनकी एक बैठक हुई थी और इस मामले की गंभीरता को लेकर उस पर चर्चा की थी कि इससे किस-किस तरह से निपटना है। उसी में एसडीएफ जो हमारे हाथ में है और पिछले 54 वर्ष के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, हम लोगों ने एसडीएफ से करीब 412 करोड़ रुपया किसानों की मदद के लिए दिया और इसमें अकेले किसानों के केन ड्यूज के ऊपर ये सारे निर्भर हैं। दूसरा आपने कहा है कि प्राइवेट मिल मालिकों से वसूली क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के ऊपर जो केन ड्यूज बकाया हैं वे 316.14 करोड़ के हैं। यानी 77 परसेंट बकाया है। कोआपरेटिव सैक्टर सरकार के पास ही होता है, उसमें 515.98 करोड़ रुपया देना बाकी है यानी 70 फीसदी इसमें ड्यूज बचे हैं, जो प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं और हमारे हाथ में जो अधिकार है, उसमें जो केन ड्यूज बचे हैं, बैलेंस बचा है, उनको पे करना था 2,970 और बचे हैं 772.29...( **व्यवधान** )...

**श्री मोतीलाल वोरा :** क्या... ( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति :** यह गणित का सवाल है। ...( **व्यवधान** )... यह गणित का सवाल है। आप बोलने दीजिए ...( **व्यवधान** )... क्या कर रहे हैं, आप।

SHRI MOTILAL VORA : I am not disputing the figures. आप कहिए।

**श्री शरद यादव :** जो बैलेंस बचा है, जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है वह 772 करोड़

रुपया है, यानी 26 परसेंट। अब सभापति जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001-02 में जो ड्यूज बचे हैं वे 24 करोड़ के हैं। जो बहुत ज्यादा थे और जिसे कौशिक जी हमेशा उठाते थे, वह सिर्फ 24 करोड़ बचे हैं। इसमें 2000-2001 के और पहले के एरियर्स 57 करोड़ हैं और कुल मिलाकर 82 करोड़ बचे हैं। वर्ष 2002-2003 के उत्तर प्रदेश के करेंट सीजन के ड्यूज 1139 करोड़ बचे हैं और यह इस सीजन में हमेशा बचते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैसे पिछली बार के ड्यूज को हमने मजबूती से उन को दिलाने का काम किया है, इस बार भी करेंगे। महोदय, अकेले इस सीजन में नहीं, ड्यूज हर सीजन में बचते हैं, इस बार थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि सुगर में क्राइसिस है, इसलिए ड्यूज ज्यादा है।

**श्री मोती लाल वोरा** : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह कथन सत्य की परिभाषा के विपरीत है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हर सीजन में किसानों को देनदारी रहती है बल्कि हमेशा एक सप्ताह के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान होता रहा है। अब सात महीने का समय बीतने आ रहा है और माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वह मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिन किसानों ने गन्ना पैदा किया और मिलों को दिया और मिल मालिक उन को सात-सात महीने तक भुगतान न करें, यह निश्चित रूप से अफसोस की बात है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में कार्यवाही करें।

**श्री शरद यादव** : महोदय, मैं एक बात कह दूं। इन्होंने ठीक बात पूछी, मैं इनकी बात का ठीक जवाब दे दूं। वर्ष 1999-2000 में जो एरियर्स बकाया थे, वे 1083 करोड़ थे, 2000-2001 में 1386 करोड़ और 2001-2002 में 2393 करोड़ थे।

**श्री सभापति** : आप तो यह बता दीजिए कि ये जिस समय गवर्नर थे, उस समय कितना बकाया था।

**श्री मोती लाल वोरा** : मैं बताऊंगा।

**श्री शरद यादव** : मैं वोरा जी से कह रहा हूं कि यह परंपरा एक दिन की नहीं है। मैं आप के जमाने के फिगर आपको पहुंचा दूंगा। ...( **व्यवधान** )... आप ठीक कह रहे हैं कि पेमेंट जल्दी होना चाहिए, आप की बात ठीक है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन लगातार परंपरा रही है। आप के जमाने में भी सरकार रही है, मैं उस के ड्यूज भी आप के पास पहुंचा दूंगा।

**श्री राजनाथ सिंह** : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के किसानों का यह मामला बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। यह बात सच है कि वर्ष 97 से यह प्रकरण कभी हाईकोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन अदालत में विचाराधीन होने के कारण मैं ऐसा महसूस कर

रहा हूं और मैं ही नहीं उत्तर प्रदेश का किसान भी यह महसूस कर रहा है कि चीनी मिल मालिकों की मनमानी काफी हद तक बढ़ गयी है। महोदय, इस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। लेकिन संविधान पीठ के समक्ष मामला यह नहीं है कि चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए, बल्कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि मूल्य निर्धारण का काम राज्य सरकारें करेंगी या केन्द्र सरकार करेगी ? महोदय, यह प्रकरण 97 से चल रहा है। इसके पहले जब भी गन्ने की कीमत निर्धारित हुई है, उस का भुगतान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने बराबर कराया है, लेकिन इस बार उस का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी और सहकारी मिलें तो भुगतान 95 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रहीं हैं जो कि निर्धारित है। महोदय, उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहकारी मिलें ...( **व्यवधान** )... मेरी एक बात सुन लीजिए।

**श्री सभापति** : आप सवाल करिए।

**श्री राजनाथ सिंह** : महोदय, मैं उस पर आ जाता हूं। मैंने बकाया की बात कही है।

**श्री सभापति** : आप सवाल कीजिए।

**श्री राजनाथ सिंह** : श्रीमन्, क्षमा चाहूंगा, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।

**श्री सभापति** : आप लंबा मत कीजिए, आप सीधा सवाल कीजिए। यह तो माननीय सदस्यों को मालूम है।

**श्री राजनाथ सिंह** : नहीं, सर, मालूम नहीं है। मेरा यह कहना है कि सरकारी और सहकारी मिलें तो 95 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से दे रही हैं, ...

**श्री सभापति** : वह तो मंत्री जी ने बता दिया है।

**श्री राजनाथ सिंह** : लेकिन, श्रीमन्, जो प्राइवेट शुगर मिल हैं वे कोई 75 रुपए, कोई 70 रुपए, कोई 96 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही हैं। इस प्रकार से गन्ने की दोहरी कीमत हो जाने के कारण साफ है कि चीनी की भी दोहरी कीमत हो जाएगी। जो सरकारी और सहकारी चीनी मिलों से चीनी पहुंचेगी उसकी कीमत ज्यादा होगी।

**श्री सभापति** : राजनाथ सिंह जी, आप भाषण मत कीजिए, क्वैश्चन करिए ...( **व्यवधान** )... सीधे क्वैश्चन करिए।

**श्री राजनाथ सिंह** : सर, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। ...( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति** : आप क्वैश्चन करिए। मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।

**श्री राजनाथ सिंह** : सर, मैं क्वैश्चन कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि ...( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति :** आप सीधे क्वैश्चन करिए।

**श्री राजनाथ सिंह :** सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। ...( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति :** लेकिन अभी तक क्वैश्चन आया ही नहीं ...( **व्यवधान** )...

**श्री राजनाथ सिंह :** सभापति जी, यथार्थ में किसानों की वेदना मेरे मन के अंदर भी है। किसानों का कोई मसीहा बनने की कोशिश न करे। ...( **व्यवधान** )... मेरे मन के अंदर भी वेदना है। ...( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति :** आपका क्वैश्चन खत्म। श्री रमा शंकर कौशिक ...( **व्यवधान** )... आप बैठिए, बैठिए।

**श्री रमा शंकर कौशिक :** श्रीमन् ...( **व्यवधान** )... सभापति जी ने मुझे बोल दिया है।

**श्री राजनाथ सिंह :** सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हमारी भारत सरकार के द्वारा जो ...( **व्यवधान** )... श्रीमन्, यह क्या हो रहा है ? यदि आप नहीं बोलने देंगे तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। श्रीमन्, यह क्या तरीका है। ...( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति :** देखिए, एक मिनट। ...( **व्यवधान** )... माफ करिए। ...( **व्यवधान** )...

**श्री राजनाथ सिंह :** सर, मेरे मन में वेदना है।

**श्री सभापति :** एक मिनट, ठहरिए। यह बोलने के अधिकार पर किसी को आपत्ति नहीं है, मगर यह क्वैश्चन आवर है, इसमें क्वैश्चन होते हैं।

**श्री राजनाथ सिंह :** मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, सर।

**श्री सभापति :** हां, तो प्रश्न पूछिए। ...( **व्यवधान** )...

**श्री रमा शंकर कौशिक :** श्रीमन्।

**श्री सभापति :** एक मिनट, ठहरिए। मैं आपको बुलवाऊंगा, आप बैठिए। कवैश्चन करिए आप, राजनाथ सिंह जी।

**श्री राजनाथ सिंह :** श्रीमन्, हमारा प्रश्न यह है कि चीनी मिल मालिकों की मनमानी बढ़ गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के द्वारा भी जो मिनिमम सपोर्ट पांच रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाई गई थी, उसका भुगतान प्राइवेट शुगर मिल वाले कर रहे हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है ...

**श्री सभापति** : ठीक है, हो गया। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दे दीजिए।

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस है, मेरे पास अभी तक जो सूबे की सरकार है उसके द्वारा एक जगह से नहीं आया कि उनको कम प्राइस दी जा रही है, यदि कहीं कम प्राइस दी जाएगी और उनके पास कोई खबर हो तो निश्चित तौर पर हमारे हाथ में सामर्थ्य है कि हम कड़ाई से वह दाम दिलाने का काम करेंगे। ...( **व्यवधान** )...

**श्री रमा शंकर कौशिक** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में 49 जो फैक्टरी हैं, वे सहकारी और कार्पोरेशन के द्वारा चलाई जाती हैं और उनमें 95 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, आप मेरी निजी जानकारी को सत्य मानते हुए इस बात को देखें, यह जो सहकारी संस्था हैं और कार्पोरेशन की संस्था हैं, जो 100 में से 47 हैं, वे काश्तकारों को पैसे की जगह चीनी सप्लाई कर रही हैं। चीनी रखने की जगह काश्तकार के पास नहीं है। वे 1250 रुपए के हिसाब से चीनी उन्हें दे रहे हैं और किसान मजबूर है उसको उसी समय 1000 रुपए में बेचने के लिए व्यापारियों को। यह स्थिति हो रही है। आपकी कोई भी मिलें, चाहे वे सहकारी मिलें हों या कारपोरेशन की मिलें हों, पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं। चीनी दे रही हैं उसकी कीमत के बदले में, जिसे काश्तकार 1250 में खरीदकर1000 रुपए में दे रहा है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वहां चीनी मिलें बंद हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि .....

**श्री सभापति** : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए वरना आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाएगा।

**श्री रमा शंकर कौशिक** : आप कृपा करके यह ऐलान कर दें कि जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिलें चलती रहेंगी।

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, श्री कौशिक जी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जब तक गन्ना खेत में है तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं की जाएगी। एक तो आपके क्वेश्चन का यह जवाब आ गया।

दूसरे, जो आपने जानकारी दी है, वह जानकारी मेरे पास नहीं थी। आप यह जानकारी दे रहे हैं, मैं सूबे की सरकार से बात करके उस पर जो भी हो सकता है, वह करुंगा। जो आपने मुझसे कहा है, वह आप मुझे लिखकर दे दें। निश्चित तौर पर जब तक गन्ना खड़ा रहेगा तब तक कोई भी मिल मालिक, मिल को बंद करने का काम नहीं कर सकता।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

---